मुख्यमंत्री
बिहार

अ0स0प0स0–4610196 / मु0मं0स0,

दिनांक– 22.08.2016

आदरणीय प्रधान मंत्री जी,

आप अवगत हैं कि बिहार राज्य बहु आपदा प्रवण राज्य है तथा प्रत्येक वर्ष राज्य को कमोबेश अन्य आपदाओं के साथ–साथ बाढ़ तथा सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, जिससे संसाधनों की भारी क्षति होती है। उल्लेखनीय है कि राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। राज्य को जहाँ नेपाल के तराई क्षेत्रों में तथा अन्य प्रदेशों यथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश में हुई भारी वर्षा के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ता है वहीं अल्प वर्षापात के कारण कई जिलों को सुखाड़ का भी सामना करना पड़ता है। विगत 10 वर्षों में 2 वर्ष छोड़कर राज्य में वर्षापात 1000 एम0एम0 के औसत से भी कम हुआ है, जो चिन्ताजनक है।

इस वर्ष जुलाई माह में नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी वर्षा से महानंदा, कनकई, बकरा, परमान, कोसी, बूढ़ी गंडक एवं गंडक आदि नदियों में काफी जल प्रवाह बढ़ गया जिसके कारण उत्तरी बिहार के 14 जिलो में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस बाढ़ के कारण कुल 78 प्रखंडों के अंतर्गत 640 पंचायतों के 2361 गाँव की 33 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई। प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 5.10 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हुई एवं 16760 घर ध्वस्त हुए। इसके अतिरिक्त इस बाढ़ के कारण 95 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं सार्वजनिक सम्पत्ति का व्यापक नुकसान हुआ। अगस्त माह में फल्गु नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण राज्य के गया, नालन्दा एवं जहानाबाद जिले प्रभावित हुए। झारखंड एवं मध्यप्रदेश में हुई भारी वर्षा के कारण क्रमशः मोहम्मदगंज बराज तथा बाणसागर डैम से छोड़े गए पानी के कारण दक्षिण बिहार से गुजरने वाली सोन नदी में पानी का काफी अधिक प्रवाह हुआ है, जो दिनांक 19.08.2016 को अचानक बढ़कर 11.67 लाख क्यूसेक से अधिक हो गया। सोन नदी में जल प्रवाह के इस बढ़े जल स्तर के कारण सोन नदी के किनारे बसे जिलो में बाढ़ का गंभीर संकट तो उत्पन्न हुआ ही, इससे गंगा का भी जल स्तर काफी बढ़ गया। गंगा नदी के सटे राज्य के 12 जिलों का बड़ा भू–भाग प्रभावित हुआ है। प्राप्त सूचनानुसार उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में हुई वर्षा ने गंगा को अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति में ला दिया है जो कि केन्द्रीय जल आयोग के आकड़ो से भी सम्पुष्ट होता है। वर्तमान में बिहार के अधिकतर स्थलों पर गंगा खतरे के निशान से उपर बह रही है। बाढ़ प्रभावितों के बीच राज्य सरकार द्वारा भारी पैमाने पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है जिसमें एन0डी0आर0एफ0 तथा राज्य के अपने बल एस0डी0आर0एफ0 की मदद ली गयी है। अभी हम लोगों ने एयरफोर्स एवं सेना को सतर्क कर दिया है एवं आवश्यकता होने पर उनकी मदद लेंगे।

सोन एवं गंगा में आयी बाढ़ के कारण फसलों एवं घरों की वृहद पैमाने पर क्षति हुई है एवं सार्वजनिक सम्पत्ति तथा पशुधन को भी व्यापक नुकसान पहुँचा है। अभी हमारा ध्यान बाढ़

प्रभावितों एवं मवेशियों को बाढ़ के पानी से निकालकर राहत शिविरों में पहुँचाने पर है। जब पानी कम होगा तब बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वेक्षण होने पर इस बाढ़ आपदा से हुई क्षति की पूरी तस्वीर उभरेगी।

जहाँ राज्य को एक तरफ बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर राज्य के कुछ हिस्सों में अल्प वर्षापात के कारण सूखे की स्थिति भी बन रही है। आज तक राज्य में सामान्य वर्षापात 719.9 एम0एम0 के विरूद्ध 615.6 एम0एम0 वर्षापात दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 14 प्रतिशत कम है। 15 अगस्त 2016 तक राज्य के 152 प्रखण्डों में 40 प्रतिशत से अधिक वर्षापात की कमी हुई है, जिसके कारण खरीफ फसल के प्रभावित होने की सम्भावना है। राज्य सरकार द्वारा फसलों को लगाने एवं खड़ी फसलों को बचाने के लिए किसानों को डीजल अनुदान दिया जा रहा है। विगत कई वर्षों से खरीफ तथा रबी दोनों ही फसलों के लिए किसानों को डीजल अनुदान दिया जा रहा है।

वर्तमान में गंगा नदी में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का मुख्य कारण फरक्का बराज के निर्माण के फलस्वरूप गंगा नदी में गाद का काफी जमाव है। इसके नदी के तल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। फलस्वरूप गंगा नदी के जल प्रवाह क्षमता में ह्रास हुआ है। गंगा नदी के तल के ऊँचा हो जाने के चलते बाढ़ 2016 की अवधि में गाँधी घाट तथा हाथीदह में पुराने उच्चतम जल स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई एवं नया उच्चतम जल स्तर बना। फरक्का बराज के निर्माण के चलते गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के फलस्वरूप वर्ष 2013 में ही भागलपुर के निकट गंगा नदी का उच्चतम जल स्तर का रिकॉर्ड भंग हुआ एवं यह 34.20 मीटर से बढ़ कर 34.50 मीटर हो गया। बिहार की नदियों में नेपाल से आने वाले गाद तथा फरक्का बराज के निर्माण के कारण गंगा नदी में गाद में जमाव की समस्या की ओर पूर्व में अनेकों बार केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है तथा इसके समाधान के लिए राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिस कारण बिहार को बाढ़ की समस्या लगातार झेलनी पड़ रही है एवं बिहार का जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि गंगा नदी में गाद के जमाव के चलते इसका तल ऊँचा हो जाने की स्थिति में कम जलश्राव में ही N.S.L (Natural Surface Level) पर पानी पहुँच जाता है और गंगा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी में गाद जमा हो जाने के चलते इसकी Meandering प्रवृति में वृद्धि हुई है, जिसके चलते नदी तट के कटाव में तेजी आई है।

विदित हो कि मैंने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक में ही गंगा नदी के अविरल प्रवाह और गंगा नदी में उत्पन्न गाद की समस्या को रेखांकित किया था। इसके उपरांत मैंने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण तथा अंतर्राज्यीय परिषद् एवं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठकों में भी राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति का मुददा उठाया है। मेरे पहल पर तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार द्वारा मई, 2012 में गंगा के सम्पूर्ण बिहार भाग, चौसा से फरक्का तक का हवाई सर्वेक्षण किया गया। तत्पश्चात् उनके द्वारा केन्द्रीय संस्थान Central Water And Power Research Station (CWPRS) द्वारा इस समस्या का अध्ययन कर निराकरण करने की बात कही गयी थी, परंतु अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई भारत

सरकार के स्तर से नहीं हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब तक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति गठित कर उसका कार्यान्वयन न होगा, तब तक हम नेपाल तथा पड़ोसी राज्यों में होने वाली वर्षा के कारण गंगा में बाढ़ का खतरा झेलने को विवश होंगे।

गंगा की अविरलता के बिन्दु पर यथोचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। बिहार की सीमा पर मात्र 400 cumecs जल प्रवाह आकलित है जबकि फरक्का बराज पर 1500 cumecs का प्रवाह सुनिश्चित करना है जो मुख्यतः बिहार की नदियों द्वारा प्राप्त जल से ही हो पाता है। फरक्का बराज में वांछित जल आपूर्त्ति करने की जिम्मेवारी केवल बिहार पर ही डाल दी गई है। इसके फलस्वरूप बिहार द्वारा गंगा एवं इसमें प्रवाहित होने वाली बिहार की नदियों के जल के उपयोग के नैसर्गिक अधिकार का भी हनन किया जा रहा है। आज हमें फरक्का बराज की उपयोगिता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फरक्का बराज के बनने से उत्पन्न हो रही स्थिति के दुष्परिणाम इसके लाभ से अधिक प्रतीत हो रहे है। अतः यह उचित होगा कि केन्द्र सरकार फरक्का बराज को हटाने के बिन्दु पर गंभीरता से विचार करे।

मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि गंगा की निर्मलता के साथ–साथ उसकी अविरलता पर एक समेकित दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। गंगा के साथ–साथ बिहार में उसकी सहायक नदियों के निर्मलता एवं अविरलता स्थापित करने की एक समग्र रणनीति को अपनाना होगा ताकि गंगा के प्रवाह एवं इसके नैसर्गिक गुणों को पुनर्स्थापित किया जा सके। कई मायने में गंगा नदी पूरे उत्तर भारत के साथ–साथ देश की भी जीवन रेखा है, इसकी स्वच्छता, संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जो भी प्रयास किये जायेंगे वो दीर्घ काल में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होंगे और बिहार सरकार ऐसे सभी प्रयासों में पूर्ण सहयोग करेगी।

अतएव मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वर्तमान बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति का सामना करने हेतु बिहार को समुचित केन्द्रीय सहायता दी जाए तथा केन्द्र से उच्च स्तरीय तकनीकी टीम भेज कर गाद प्रबंधन नीति के दृष्टिकोण से गंगा की वर्त्तमान जल प्रवाह की स्थिति का आकलन इसी समय करवा लिया जाए। इससे गंगा नदी की अविरलता में अवरोध, अप्रत्याशित गाद का जमाव तथा वर्तमान परिस्थिति में फरक्का बराज के औचित्य का आकलन किया जा सकेगा। आशा है जो मुद्दे हमारी तरफ से उठाये गये हैं उन पर सकारात्मक विचार कर केन्द्र सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिये जायेंगे।

सादर,

आपका,

(नीतीश कुमार)

श्री नरेन्द्र मोदी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।